

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)पीठासीन अधिकारी - तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 003/2013 (GCMS 2013/00015)	दायर दिनांक 06.02.2013	निर्णय दिनांक 14.12.2021
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

1. जयचन्द पिता खेमा जाति पूर्बिया गाडरी उम्र 70 वर्ष निवासी शिवगढ नेतावल महाराज तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. चुन्नीलाल पिता रामाजी जाति पूर्बिया गाडरी उम्र 60 वर्ष निवासी शिवगढ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बालु पिता परथु जाति चमार उम्र बालिग निवासी शिवगढ नेतावल महाराज तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :- आरसी दशोरा	अधिवक्ता प्रार्थी
आरसी शर्मा	अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

कार्यवाही अन्तर्गत धारा (14) (4) राजस्थान कृषि भूमि प्रयोजनार्थ
आवंटन नियम 1970 भू-आवंटन पत्रावली संख्या 17/76 तारीख
आवंटन दिनांक 12.01.1977

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू0 आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत खिलाफ अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शिवगढ नेतावल महाराज तहसील चित्तौड़गढ़ की हाल खेवट खतौनी संख्या 246 में अंकित हाल आराजी संख्या 162 रकबा 0.62 हैक्टेयर एवं हाल आराजी संख्या 163 रकबा 0.53 हैक्टेयर कुल किता रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि जिसके गत भू-माप संख्या 1596/649 थी। उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 को पत्रावली संख्या 17/76 दिनांक 12.01.1977 को 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटन किये जाने एवं नामान्तरकरण संख्या 420 दिनांक 04.06.1977 को राजकीय भूमि को गैर खातेदारी में विपक्षी संख्या 1



82
(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

के नाम दर्ज करने में भारी कानूनी भूल की है। जिसमें आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन से पूर्व पटवारी हल्का ने तथ्यों को छिपाकर आवंटन किये जाने की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। गत भू-माप की आराजी संख्या 1596/649 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि के पूर्व दिशा में श्मशान घाट बना हुआ है और करीब 15 बिस्वा भूमि पर ग्राम शिवगढ के नागरिक श्मशान घाट पर मृत व्यक्तियों के दाह-संस्कार करते हैं जो करीब 100 वर्षों से अधिक समय से उक्त भूमि श्मशान घाट के उपयोग-उपभोग में चिर स्थाई रूप से करते चले आ रहे हैं। उक्त तथ्य को पटवार हल्का ने अपनी रिपोर्ट में छिपा कर गलत रिपोर्ट तैयार कर विपक्षी संख्या 1 को अनाधिकृत रूप से लाभ पहुँचाने की बद्नियंती से भूमि आवंटन की सिफारिश की है जो न्याय, नियमों एवं वाक्याती तथ्यों के विपरित होकर उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 ने विधिवत आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग-उपभोग में काम में ली जा रही थी। आवंटन हेतु रिक्त (खाली) भूमि भी नहीं थी। विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी में 10 बीघा भूमि से भी अधिक भूमि है। विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आता है। उक्त भूमि आवंटन किये जाने हेतु विधिवत उद्घोषणा भी जारी नहीं हुई थी तथा आवंटन के वक्त आवंटन हेतु विधिवत कौरम भी नहीं हुई थी तथा विपक्षी संख्या 1 का आवंटित भूमि में से 15 बिस्वा भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। आज भी उक्त भूमि श्मशान हेतु उपयोग में ली जा रही है। विपक्षी संख्या 1 का आवंटित भूमि के पूर्व दिशा में 15 बिस्वा भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही विपक्षी संख्या 1 ने 15 बिस्वा भूमि जो श्मशान हेतु उपयोग-उपभोग में ली जा रही हैं। उस पर काश्त की है। विपक्षी संख्या 1 अलोटमेंट की पात्रता नहीं रखता है। आवंटन नियमों का खुला उल्लंघन का आवंटन किया गया है। सार्वजनिक उपयोग करी भूमि का आवंटन अवैध एवं प्रभाव शून्य है एवं गैर कानूनी है। विपक्षी संख्या 1 श्मशान घाट की भूमि जो कि 15 बिस्वा अवैध एवं गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने पर आमादा है और इसको लेकर फिजूल की विवाद बढ़ने की संभावना है। जनहित में विपक्षी संख्या 1 का आवंटन किये जाने से 15 बिस्वा भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित है जो सार्वजनिक हित में है। आवंटन आदेश नियमों के विरुद्ध है तथा भू-आवंटन के नियमों का उल्लंघन कर भू-आवंटन किया गया है। जिन लोगों से भूमि सिलिंग में प्राप्त की गई थी उन लोगों ने भी भूमि श्मशान घाट हेतु ग्राम वासियान को सौंप रखी थी। ग्रामवासियान को आवंटन से पूर्व किसी प्रकार की सूचना तक नहीं दी गई तथा गुप्तरूप से आवंटन किया गया है। आवंटन की जानकारी प्रार्थीगण ग्रामवासियान को नहीं थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 31.12.2011 को और उसके बाद लगातार विपक्षी संख्या 1 ग्रामवासियान को श्मशान भूमि पर दाह-संस्कार करने से रोक-टोक करता है। उसके बाद विपक्षी संख्या 1 के आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की और आदेश की नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी से आवेदन प्रस्तुत है। वैसे भी अवैध एवं गैर कानूनी आदेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है और न्यायालय को ऐसे आदेश निरस्त करने का पूरा-पूरा अधिकार है। फिर भी कानूनी अडचनों से बचने के लिए धारा 5 कानून मियाद का आवेदन पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत है। अंत में



52
(सारा चन्द बीणा)
जिला कलेक्टर
जिला इगढ़

प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 12.01.1977 को भू-आवंटन संख्या 17 सन् 76 के जरिए गत भू-माप संख्या 1596/649 हाल आराजी संख्या 162, 163 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 15 बिस्वा भूमि का आवंटन निरस्त कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 28.05.2013 उनके अधिवक्ता हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 20.04.2014 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। न्यायालय आदेश दिनांक 14.07.2014 से तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्रकरण में मौका एवं रेकार्ड की संबंध में वास्तविक स्थिति के संबंध में बाद जांच रिपोर्ट के आदेश दिये गये। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/राजस्व/2016/1442 दिनांक 03.10.2016 से प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार द्वारा पत्रांक/अभिलेखागार/2021/68 दिनांक 31.08.2021 से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का मूल अभिलेख पत्रावली संख्या 17/1976 निर्णय दिनांक 12.01.1977 को प्रेषित किया गया जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है।

दिनांक 24.11.2021 को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्षकारान की सहमति से प्रकरण में बहस पत्रावली सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली में बताया कि ग्राम शिवगढ नेतावल महाराज तहसील चित्तौड़गढ़ की हाल खेवट खलौनी संख्या 246 में अंकित हाल आराजी संख्या 162 रकबा 0.62 हैक्टेयर एवं हाल आराजी संख्या 163 रकबा 0.53 हैक्टेयर कुल किता रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि जिसके गत भू-माप संख्या 1596/649 थी। उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 को पत्रावली संख्या 17/76 दिनांक 12.01.1977 को 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटन किये जाने एवं नामान्तरकरण संख्या 420 दिनांक 04.06.1977 को राजकीय भूमि को गैर खातेदारी में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज करने में भारी कानूनी भूल की है। आवंटन से पूर्व पटवारी हल्का ने तथ्यों को छिपाकर आवंटन किये जाने की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। गत भू-माप की आराजी संख्या 1596/649 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि के पूर्व दिशा में श्मशान घाट बना हुआ है और करीब 15 बिस्वा भूमि पर ग्राम शिवगढ के नागरिक श्मशान घाट पर मृत व्यक्तियों के दाह-संस्कार करते है जो करीब 100 वर्षों से अधिक समय से उक्त भूमि श्मशान घाट के उपयोग-उपभोग में चिर स्थाई रूप से करते चले आ रहे है। उक्त तथ्य को पटवार हल्का ने अपनी रिपोर्ट में छिपा कर गलत रिपोर्ट तैयार कर विपक्षी संख्या 1 को अनाधिकृत रूप से लाभ पहुँचाने की बदनियती से भूमि आवंटन की सिफारिश की है जो न्याय, नियमों एवं वाक्याती तथ्यों के विपरित होकर उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। मौजा शिवगढ नेतावल महाराज की साबिक आराजी संख्या 1596/649 रकबा



६३

(सारा चन्द भीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

5 बीघा 5 बिस्वा भूमि के पूर्व दिशा में श्मशान घाट बना हुआ है और करीब 15 बिस्वा भूमि पर ग्राम शिवगढ के नागरिक श्मशान घाट पर मृत व्यक्तियों के दाह-संस्कार करते हैं जो करीब 100 वर्षों से अधिक समय से उक्त भूमि श्मशान घाट के उपयोग-उपभोग में चिर स्थाई रूप से करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं होने तथा दोषपूर्ण ढंग से उक्त आराजीयात को अनाधिकृत (खाली) दिखाकर राजस्व भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियमों के विपरीत उक्त आवंटन आदेश पारित किया जो कि काबिल निरस्त योग्य है।

इसके जवाब में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम नेतावल महाराज की गत भू-माप आराजी संख्या 1596/649 के हाल खेवट खतौनी संख्या 246 में अंकित हाल आराजी संख्या 162 रकबा 0.62 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 163 रकबा 0.53 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल किता रकबा 1.15 हैक्टेयर स्थित नेतावल महाराज विधिवत रूप से आवंटन समिति द्वारा आवंटन कर मौके पर भौतिक कब्जा सिपुर्द किया गया तथा आवंटन शुदा आराजीयात नामान्तरकरण संख्या 420 दिनांक 04.08.1977 की विपक्षी संख्या 1 के नाम से गैर खातेदारी में दर्ज की गई और उसके पश्चात् खातेदारी में दर्ज होकर उक्त आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 काबिज होकर काशत कर रहा है। तथा विपक्षी संख्या 1 के नाम आवंटन वैध व कानूनन सही किया गया है जो निरस्त नहीं किया जा सकता है। गत भू-माप की आराजी संख्या 1596/649 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा के पास श्मशान घाट नहीं होकर काफी दूर है तथा शिवगढ के ग्राम वासियान मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार विपक्षी संख्या 2 की आराजीयात से काफी दूर पर करते हैं तथा विपक्षी संख्या 1 की आराजी से श्मशान काफी दूर पर स्थित है और इसमें पटवार हल्का निष्पक्ष रूप से विपक्षी संख्या 1 आवंटन का पात्र होने से रिपोर्ट सही तथ्य अंकित कर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार आधारों पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है। विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन होने तथा अनुसूचित जाति का सदस्य होने से तथा आवंटनशुदा भूमि पर काफी सालों से विपक्षी संख्या 1 का कब्जा होने तथा आराजी किसी प्रकार से सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित नहीं होने से विधिवत सही जांच की जाने के पश्चात् ही आवंटन की गई है। यदि विपक्षी संख्या 1 को आवंटन की गई आराजी श्मशान घाट के उपयोग में होती तो पटवार हल्का उक्त तथ्य को अपनी रिपोर्ट में अंकित कर ग्राम पंचायत एवं ग्राम वासियान नेतावल महाराज व शिवगढ के ग्रामवासियों द्वारा वक्त आवंटन एतराज आपत्ति करते किन्तु पटवार हल्का की रिपोर्ट सही होने से आवंटन समिति द्वारा विधिवत आवंटन कर भौतिक कब्जा देकर गैर खातेदारी में दर्ज हुई है तथा उसके बाद खातेदारी में दर्ज हुई जो आज भी आराजीयात विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी व कब्जेकाशत में चली आ रही है। आवंटन विधिवत होने से निरस्त नहीं किया जा सकता है। श्मशानघाट विपक्षी संख्या 1 को आवंटनशुदा आराजीयात से काफी दूर स्थित है। विधिवत उद्घोषणा जारी होकर विधिवत कौरम में विपक्षी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी आवंटन की गई है जिस पर विपक्षी खातेदार काशतकार हो कब्जेकाशत में चली आ रही है। श्मशान घाट की



25
(हारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
जयसिंग

भूमि बिल्कुल अलग होकर सुरक्षित है जिस पर शिवगढ के ग्रामवासी मृतक व्यक्तियों का दाह संस्कार कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार से कानूनी उल्लंघन नहीं हुआ है। विपक्षी संख्या 1 का आवंटन वैध व प्रभावशील व कानूनी है जो भूमि आवंटन समिति द्वारा विधिवत रूप से विपक्षी संख्या 1 को पात्रता के आधार पर आवंटन की गई है, उस भूमि में श्मशान घाट की एक इंच भूमि भी नहीं है। उक्त भूमि काश्त योग्य है तथा श्मशान के नाम से भी कहीं दर्ज नहीं है। जिन लोगों द्वारा सिलिंग में भूमि गई वह भूमि ग्रामवासियों को श्मशान के लिए दी गई वह भूमि विपक्षी संख्या 1 को आवंटन की भूमि से न तो लगी हुई है न श्मशान भूमि लगी है। प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध द्वैषतावश उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 को जो भूमि आवंटन हुई है उसकी नेतावल महाराज व शिवगढ के नागरिकों को पूर्णतया जानकारी है जो भूमि दाह संस्कार के लिए सुरक्षित है और जहां आज भी दाह संस्कार किए जा रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 ने कभी भी दाह संस्कार श्मशान भूमि में करने से इनकार नहीं किया है। दाह संस्कार की सुरक्षित भूमि से विपक्षी संख्या 1 का कोई सरोकार नहीं है। विपक्षी संख्या 1 को भूमि पात्रता के आधार पर आवंटन किया गया है। इसके साथ ही प्रार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ के न्यायालय में वादग्रस्त आराजीयात के लिए धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि प्रकरण संख्या 68 सन् 2012 दर्ज हुआ जो प्रार्थना पत्र श्मशान की भूमि विपक्षी संख्या 1 को आवंटन की गई भूमि में नहीं होने व सबूत के अभाव में प्रमाणित नहीं होने से दिनांक 20.11.2012 को प्रार्थीगण का आवेदन खारीज फरमाया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारीज हो जाने के पश्चात् द्वैषतावश प्रार्थीगण ने न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 1 को जलील व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है जो आधारहीन, बेबुनियाद सही तथ्यों को छुपाकर पेश किया गया है जो निरस्त फरमाया जावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने तर्क के समर्थन में RRT 2016(2) पेज संख्या 884, RRT 2018(2) पेज संख्या 1007, RRT 2018(1) पेज संख्या 285 एवं RRT 2016(2) पेज संख्या 756 न्यायिक दृष्टांत पेश किये एवं दृष्टिपात कराया एवं निवेदन किया कि उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में प्रार्थी/निगराकार का प्रार्थना पत्र सब्यय खारीज फरमाया जावे।

इस पर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 (राजकीय अधिवक्ता) ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर आवंटन नियमों की पूर्ण पालना की जाकर विधिवत आवंटन किया गया है जिससे अधीनस्थ आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय दिनांक 12.01.1977 में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये जाने की गुंजाईश नहीं होकर पुष्टि किये जाने योग्य है। अतः उक्त प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि विपक्षी संख्या 1 ने विधिवत आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ



23
(सारा चन्द मीणा)
जिला कलकत्ता
चित्तौड़गढ

उपयोग-उपभोग में काम में ली जा रही थी। आवंटन हेतु रिक्त (खाली) भूमि भी नहीं थी। विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी में 10 बीघा भूमि से भी अधिक भूमि है। विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आता है। उक्त भूमि आवंटन किये जाने हेतु विधिवत उद्घोषणा भी जारी नहीं हुई थी तथा आवंटन के वक्त आवंटन हेतु विधिवत कौरम भी नहीं हुई थी तथा विपक्षी संख्या 1 का आवंटित भूमि में से 15 बिस्वा भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। आज भी उक्त भूमि श्मशान हेतु उपयोग में ली जा रही है। विपक्षी संख्या 1 का आवंटित भूमि के पूर्व दिशा में 15 बिस्वा भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही विपक्षी संख्या 1 ने 15 बिस्वा भूमि जो श्मशान हेतु उपयोग-उपभोग में ली जा रही हैं। उस पर काश्त की है। विपक्षी संख्या 1 अलोटमेंट की पात्रता नहीं रखता है। आवंटन नियमों का खुला उल्लंघन का आवंटन किया गया है। सार्वजनिक उपयोग करी भूमि का आवंटन अवैध एवं प्रभाव शून्य है एवं गैर कानूनी है। विपक्षी संख्या 1 श्मशान घाट की भूमि जो कि 15 बिस्वा अवैध एवं गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने पर आमादा है और इसको लेकर फिजूल की विवाद बढ़ने की संभावना है। जनहित में विपक्षी संख्या 1 का आवंटन किये जाने से 15 बिस्वा भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित है जो सार्वजनिक हित में है। आवंटन आदेश नियमों के विरुद्ध है तथा भू-आवंटन के नियमों का उल्लंघन कर भू-आवंटन किया गया है। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 12.01.1977 को भू-आवंटन संख्या 17 सन् 76 के जरिए गत भू-माप संख्या 1596/649 हाल आराजी संख्या 162, 163 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 15 बिस्वा भूमि का आवंटन निरस्त कराया जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने तर्क के समर्थन में RRD 1982 पेज संख्या 237, RRD 1981 पेज संख्या 644, RRD 1983 पेज संख्या 53, RRD 1983 पेज संख्या 319 एवं RRD 1989 पेज संख्या 654 न्यायिक दृष्टांत पेश किये एवं न्यायिक दृष्टांत पर दृष्टिपात कराया एवं प्रार्थी/निगराकार का प्रार्थना स्वीकार किये जाने की ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत शामिल पत्रावली है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस का मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :-

101. Allotment of land for agricultural purposes - (1) Save as otherwise provided elsewhere by this Act, lands for agricultural purposes shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government in this behalf.



८६
(सारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
जयपुर

(2) All allotment of land under this section shall be subject to the payment of rent fixed at such rates as may be fixed according to custom or by usage or any law on the subject.

(3) XXX delted XXX]

(4) If there be more than one person requiring the same land, the allotment shall be made in the following order –

- (i) to co-sharer of the holding if it forms part of a compact block or is irrigated from the same source, preference amongst such co-sharers being given to one having land less than the area prescribed by rules made under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955);
- (ii) to persons residing in the village in which land be situated, preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescribed by the said rules;
- (iii) by drawing lots;]

Provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules.

14. Condition of Allotment. –

- (1) The allotment of land under these rules shall be on a Gair Khatedari tenancy with a right to ultimate conferment of Khatedari rights after the expiry of 10 years provided the allottee fulfills during this period the terms and conditions of allotment until Khatedari rights are conferred. The allottee shall have all the rights and be subjected to all liabilities of a Gair Khatedar tenant under the Tenancy Act:
[Provided also that the allotment of land may be cancelled at any stage by the Collector before the expiry of a period of 10 years, if the land is required for public purpose:
[Provided further the no such order to the prejudice of such person shall be passed without giving him an opportunity of being heard.]
- (2) Rent at the sanctioned rent rate applicable to the land, or if the land applied for and allotted is unassessed, at the lowest class of Barani land in the village for irrigated land at the Chahi or Nehri rates, as the case may be. for Chahi or Nehri irrigated lands of the village shall be payable from the first year of allotment.
- (3) The allottee shall have to cultivate at least 50% of the land in the first year- of allotment and the remaining area in the second year: Provided that this period may be extended by the Tehsildar by one year if, due to unforeseen causes over which the allottee had no control, he was unable to cultivate the land within the stipulated period.
- (4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office [or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules] either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:
Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.
- (5) The allottee shall pay to the State Government the price of the walls and permanent structures if any, existing on the land, as also the price of trees standing on the land at rates prescribed by rules made under section 80 and 81 of the Tenancy Act.
- (6) Before acquisition of Khatedari rights the allottee shall not construct any permanent structures or buildings other than a tank, well or dwelling a house within the meaning of an "improvement" as defined by clause (19) of section 5 of the Tenancy Act.



८३
(सारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
जिला इगद

- (7) In case of land situated within a radius of 10 miles of Jaipur City the allottee shall also pay the rate of Fifteen rupees and 25 paise per hi glia:
Provided that, no such price shall be charged if the number of trees standing in a bigha of land is less than five.
- (8) The land shall be liable to be resumed by the State Government without, payment of compensation if-
- it is not brought under cultivation strictly in accordance with the condition of allotment and it is not properly utilised:
 - it is sub let or transferred in contravention of the provision of Tenancy Act applicable to Gair Khatedar tenants:
 - it is found that the allottee was not a (landless agriculturist);
 - the allottee makes default in the timely payment of the price referred to in clause 5 of the rule and/or the annual rent: or
 - the allottee makes construction on the land in contravention of the allotment rules.
- [(9) In case the land allotted in grass land or subject to erosion, the allottee shall have to undertake the work of soil conservation as and when directed by an officer of the Agriculture Department authorised in this behalf.]

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि आवंटन किये जाने हेतु विधिवत उद्घोषणा भी जारी नहीं हुई थी तथा आवंटन के वक्त आवंटन हेतु विधिवत कौरम भी नहीं हुई थी तथा विपक्षी संख्या 1 का आवंटित भूमि में से 15 बिस्वा भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। आज भी उक्त भूमि श्मशान हेतु उपयोग में ली जा रही है। विपक्षी संख्या 1 का आवंटित भूमि के पूर्व दिशा में 15 बिस्वा भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही विपक्षी संख्या 1 ने 15 बिस्वा भूमि जो श्मशान हेतु उपयोग-उपभोग में ली जा रही हैं। विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने से भूमि आबाद नहीं करने से आवंटन आदेश जो वैधानिक रूप से भी गलत है, जो निरस्त होने योग्य है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा अवगत कराया गया है आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को सूचना दी, तथा राज्य सरकार द्वारा जो सदस्य नियुक्त किया गया है, उन सदस्यों ने समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए राज्य सरकार के आदेशानुसार आवंटन किया है, जो सही एवं सत्य है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन आदेश किया है उससे पूर्व ही अप्रार्थीगण का कब्जा हो काश्त करता चला आ रहा है, तथा काफी अंग मेहनत करके उक्त भूमि को उपजाऊ बनाकर कृषि कार्य कर रहा है तथा जिस जगह कृषि भूमि आवंटन हुई उसी जगह काश्त करता चला आ रहा है, तथा उक्त भूमि पर कदीम से प्रार्थी का कब्जा हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। हमने तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा कि वर्तमान आराजी संख्या 162 रकबा 0.62 हैक्टेयर व आराजी संख्या 163 रकबा 0.53 हैक्टेयर के गत आराजी संख्या 1596/649 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा थे। गत आराजी संख्या 1596/649 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा में से 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि बालु पिता परथु चमार के नाम आवंटन हुई। जिसके अनुसार 1.13 हैक्टेयर भूमि बनती है। इस प्रकार बालु पिता परथु के वर्तमान रिकार्ड अनुसार 0.02 हैक्टेयर भूमि बेशी हुई है। गत आराजी संख्या 1596/649 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि राजकीय बिलानाम काबिल



८३
(सारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर

काश्त दर्ज रिकार्ड थी। मौतबिरानों के अनुसार उक्त 0.02 हैक्टेयर बेशी भूमि पर वर्षों से मजरा-शिवगढ़ वाले ग्रामवासियों द्वारा श्मशान हेतु उपयोग में ली जा रही है। इस संबंध में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा वर्तमान में मौके पर श्मशान हेतु उपयोग में आ रही भूमि 0.02 हैक्टेयर का नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा इस संबंध में पर्चा मौका प्रति दिनांक 21.04.2014 प्रस्तुत की गई। पर्चा मौका दिनांक 21.04.2014 में खातेदार को उक्त भूमि श्मशान हेतु उपयोग में ली जाती है तो उनको कोई आपत्ति नहीं होना अवगत कराया गया।

अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटी को भूमि का कब्जा पटवार हल्का द्वारा दिनांक 28.07.1976 को सौंपा जा चुका था। आवंटी का आवंटित भूमि पर उसी का कब्जा होकर उपयोग/उपभोग में ली जा रही है। विपक्षी ने कब्जा एवं काश्त नहीं की है, किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं हो पाया है। जहां तक गैर खातेदारी से खातेदारी का प्रश्न है कृषि भूमि हेतु भू-आवंटन नियम 1970 के प्रावधान अनुसार आवंटी खातेदारी की पात्रता रखता है। आवंटन के 35 वर्षों बाद भूमि आवंटन निरस्तगी के प्रार्थना पत्र का कोई पुख्ता अभिलेखीय आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। 35 वर्ष पूर्व भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ हुआ, जिस पर काश्त की जा रही है। उक्त विवरण के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या आधार पर प्रस्तुत हुआ जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा जो तथ्य प्रार्थना पत्र में उठाए गए हैं वे पूर्ण रूप से मिथ्या हैं। विधिवत भूमि की उद्घोषणा जारी होकर सलाहकार समिति की राय के अनुसार आवंटन किया गया है। प्रथम दृष्ट्या तो आवंटित भूमि पर कब्जा प्रार्थी का प्रमाणित नहीं है। यदि कब्जा प्रार्थी का माना भी जाये तो प्रार्थी अतिचारी की श्रेणी में आता है। विपक्षीगण को भूमि का आवंटन विधिवत किया जाना प्रस्तुत अभिलेख से प्रतीत है। छल-कपट या नियमों के विपरीत भूमि आवंटन का होना नहीं पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन व आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 017/1976 दिनांक 12.01.1977 में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं अप्रार्थी बालु पिता परथु चमार का आवंटन यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित होना पाया जाता है कि आवंटी को आवंटन समिति द्वारा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है एवं वर्तमान में आवंटी के नाम पर दर्ज राजस्व रेकार्ड अनुसार कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर दर्ज अभिलिखित है। इस प्रकार 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि का भू-प्रबंध के बाद नवीन नाप अनुसार रकबा 1.13 हैक्टेयर ही होना चाहिये था जबकि आवंटी के नाम पर वर्तमान में 1.15 हैक्टेयर दर्ज अभिलिखित है ऐसी स्थिति में यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि आवंटी के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में 0.02 हैक्टेयर भूमि अधिक दर्ज रेकार्ड है। रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ अनुसार उक्त अधिक दर्ज रेकार्ड भूमि



६६
(सारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

पर वर्तमान में श्मशान स्थित है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 के वर्तमान में अपनी खातेदारी में दर्ज आराजीयात आराजी संख्या 163 रकबा 0.53 हैक्टेयर मैसे 0.02 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं होना प्रमाणित होता है, ऐसी स्थिति में उक्त आराजी संख्या 163 रकबा 0.53 हैक्टेयर मैसे 0.02 हैक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 017/1976 दिनांक 12.01.1977 में आंशिक संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं अप्रार्थी बालु पिता परथु चमार के नाम पर दर्ज आराजी संख्या 163 रकबा 0.53 हैक्टेयर मैसे 0.02 हैक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा शेष आवंटन यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी जयचन्द पिता खेमा गाडरी निवासी शिवगढ़ नेतावल महाराज वगैराह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 में आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 017/1976 निर्णय दिनांक 12.01.1977 में आंशिक संशोधन किया जाता है एवं अप्रार्थी बालु पिता परथु चमार के नाम पर दर्ज आराजी संख्या आराजी संख्या 163 रकबा 0.53 हैक्टेयर मैसे 0.02 हैक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है तथा शेष आवंटन यथावत रखा जाता है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ उक्त 0.02 हैक्टेयर भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम अंकित करे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के लौटाया जावे। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 14.12.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



२३
(तारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर,
चित्तौड़गढ़